Characteristics and Delineation of Planning Region

Dr. Jagdish Chand
Assistant Professor (Geography)
Govt. College Sangarh

Year	Core Courses	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2)	Skill Enhancement Course (SEC) (2)	Discipline Specific Elective (DSE) (4)	Generic Elective GE (2)
1st	English/ MIL-1 Physical Geography (GEOGP 101 CC) DSC-2A	(English/ MIL Communication) / Environmental Science			
	English/ MIL-1 General Cartography (Practical) (GEOGP 102 CC) DSC-2B	Environmental Science/ (English/ MIL Communication)			
2nd	English / MIL-2 Human Geography (GEOGP 201 CC) DSC-2C English /MIL-2 Environmental Geography (GEOGP 202 CC) DSC- 2D		Regional Planning and Development (GEOGP 203 SEC) Remote Sensing and GPS (GEOGP 204 SEC)		
3rd			Geographic Information System (Practical) GEOGP 301 SEC)	Geography of India (GEOGP 303-1 DSE) Or Economic Geography (GEOGP 303-2 DSE)	Disaster Risk Reduction (GEOGP 305-GE 1)
			Field Techniques and Survey based Project Report (Practical) (GEOGP 302 SEC)	Disaster Management (GEOGP 304-1 DSE) Or Geography of Tourism (GEOGP 304-2 DSE)	Sustainability and Development (GEOGP 306- GE 2)

REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT (GEOGP 203 SEC)

Unit	Topic
1	Introduction, Concept, Need and Types of Regional Planning, Characteristics and Delineation of Planning Region
2	Regionalization: Concept, Hill Region: Case study of Himachal Pradesh(Physical and Cultural aspects)
3	Models for Regional Planning, Growth Pole Theory and Core Periphery Model
4	Regional Development Initiatives: Case Studies, Integrated tribal Development Programme (ITDP), Damodar Valley Corporation(DVC)

Characteristics of Planning Region

नियोजित प्रदेशों की विशेषताएं

- नियोजित प्रदेश से अभिप्राय धरातल के उस क्षेत्र विशेष से है, जिसमें आर्थिक निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है।

- इस सन्दर्भ में नियोजन का अर्थ आर्थिक विकास हेतु लिए गए आर्थिक निर्णयों एवं उनके क्रियान्वयन से है।

- नियोजन के उद्देश्य से चुना गया प्रदेश आमतौर पर प्रशासनिक या राजनैतिक ही होता है, क्योंकि नियोजन हेतु आंकड़े प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर उपलब्ध होते हैं ।

- संक्षेप में नियोजन के लिए चुना गया प्रदेश सर्म्पूण देश, राज्य, जिला तहसील एवं विकास कुछ भी हो सकता है। नियोजित के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित प्रदेश में धरातलीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता होनी चाहिए अत: नियोजित प्रदेश की सीमा के निर्धारण के लिए समांगता, नोडियता तथा प्रशासनिक सुविधा के बीच सन्तुलन की आवश्यकता होती है।

- **आकार न ही बहुत बड़ा या छोटा** (Size not so Big or Small)
- **सीमाओं में लोचशीलता** (Flexibility in Boundaries)
- **आकृति** (Shape)
- **प्राकृतिक सम्बद्धता** (Natural Cohesion)
- **आर्थिक व्यवहारिकता** (Economic Viability)

- **सामाजिक सौहृदयता** (Social Harmony)
- **प्रकार्यात्मक एकता** (Functional Unity)
- **समस्याओं में समरूपता** (Similarity of Problems)
- **क्षेत्रीय सचेतना** (Regional Consciousness)
- **प्रशासनिक सहूलियत** (Administrative Convenience)

Delineation of Planning Region

नियोजित प्रदेश का सीमांकन

सीमांकन के सिद्धान्त (Principles of Demarcation)

सीमांकन के मापदण्ड (Criteria of Demarcation)

सीमांकन की विधि (Method of Demarcation)

प्राकृतिक प्रदेशों के द्वारा नियोजित प्रदेशों का सीमांकन।

(The demarcation of planning region begins with Natural Regions)

नियोजित प्रदेशों का सीमांकन सूक्ष्म स्तर से मध्यम एवं बृहत स्तर की ओर।

(The demarcation of planning region begins with the macro level to meso and macro level.)

प्रशासनिक इकाईयों के साथ नियोजित प्रदेशों की सीमाएं मेल खा भी सकती हैं या नहीं भी।

(Planning regions boundaries may or may not conform with administrative units.)

सूक्ष्म स्तरीय, मध्य स्तरीय एवं बृहतस्तरीय प्रदेशों की सीमाएं एक-दूसरों को नहीं काटती होनी चाहिए।

(No cross cut boundaries at Micro, Meso and Macro level regions.)

नियोजित,प्रदेशों की सीमाएं स्थाई नहीं बल्कि गतिशील होनी चाहिएं।

(Boundaries of planning region should be permanent but dynamic.)

- **भूगौलिक मानचित्र** (Physiographic Maps related to Land)
- **जनसंख्यकीय मानचित्र** (Population Maps)
- **अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित मानचित्र** (Maps Associated Economy)
- **समस्याजनित मानचित्र** (Problem Oriented Maps)
- **क्षेत्रिया गतिशीलता प्रारूप तथा तीवता को दर्शाने वाले मानचित्र** (Regional Mobility Patterns and Intensity

Hierarchy of Planning Region or Three Tier System

नियोजित प्रदेश का पदानुक्रमन या त्रिस्तरीय व्यवस्था

लघु अथवा अल्पार्थिक आर्थिक प्रदेश (Micro Regions)

- यह नियोजित प्रदेश प्रादेशीकरण के विकार निम्न श्रेणी के होते हैं। स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों, महानगरीय प्रदेश अथवा परिवहन विकास की योजना बनाने प्रदेशों में किए जाते हैं।

- इन प्रदेशों की प्राकृतिक दशाओं में समानता पाई जाती है और स्थानीय जनसमुदाय की विकास में पूरी रूचि होती है।

- ये किसी एक विशिष्ट के गुण से परिर्पूण होते हैं, जैसे उत्तरी-पूर्वी भारत में चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन एवं जलविद्युत उत्पादन, पंजाब, हरियाणा कृषि प्रदेश, पर्यटन इत्यादि ।

- संक्षेप में नियोजित प्रदेश के सीमांकन में सबसे छोटे स्तर के प्रदेश होते हैं जिनका निर्धारण कम से कम एक विशिष्ट प्रकार के उत्पादन चक्र ध्यान में रखकर किया जाता है। निम्नस्तरीय प्रदेशों की पहचान आसपास के प्रदेशों की तुलना में आसानी से की जा सकती हैं।

मध्यस्तरीय प्रदेश (Meso Regions)

- यह नियोजन प्रदेश नियोजित प्रादेशीकरण के विकास में द्वितीय श्रेणी होते हैं। उनकी रचना की निम्न श्रेणी (अल्पार्थिक) के प्रदेशों को मिलाकर की जाती है।

- मध्यम स्तरीय प्रदेश नियोजन प्रक्रम के पदानुक्रम में द्वितीय श्रेणी के होते हैं तथा यह बहुउद्देशीय प्रकृति के होते हैं तथा इनमें कम से कम उत्पादन प्रक्रिया में विशिष्टता बृहत प्रदेशों के अनुरूप राष्ट्र ीय स्तर की होनी चाहिए तथा ये निम्नस्तरीय प्रदेश एवं बृहत स्तरीय प्रदेश के साथ **संगम (Nodal Prints) केन्द्रों (Nodal Centres)** के रूप में प्रादेशिक एवं राष्टीय स्तर के महत्त्वानुसार परस्पर जुड़े होने चाहिएं अमेरिका के टैनिसी घाटी परियोजना, भारत की दामोदर घाटी परियोजना मध्यम स्तरीय प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है।

- दामोदर घाटी परियोजना के तीन निम्नस्तरीय प्रदेश कोयला उत्पादन केन्द्र राष्ट्र ीय महत्त्व के उच्चवर्ती भू-भागों में वनों का आवरण तथा निम्नवर्ती नदी घाटी में कृषि योग्य भूमि क्षेत्रीय महत्त्व के निम्नस्तरीय प्रदेश

बृहत विस्तृत स्तरीय प्रदेश (Macro Regions)

- यह नियोजित प्रदेश नियोजित प्रदेशीकरण के विकास में सबसे उच्च श्रेणी के होते हैं क्योंकि यह देश के एक विस्तृत भू-भाग की महत्त्वर्पूण क्षेत्रिया आर्थिक समस्याओं के समाधान में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह अन्तर्राज्यीय प्रकृति के होते हैं। इस स्तर पर प्राकृतिक सम्पदा का विकास बहुत बड़े स्तर पर विचार विर्मश के साथ किया जाता है।

- उदाहरर्णाथ, नदी बेसिन सिंचाई व्यवस्था, शक्ति अथवा परिवहन के साधनों के विकास की योजनाएँ। यह प्रदेश प्रकृतिक सम्पदा अन्न, शक्ति के साधनों, कच्चे माल और परिवहन साधनों में आत्मनिर्भर होते हैं। इनकी प्राकृतिक दशाओं में भिन्नता पाई जाती हैं परन्तु इनमें आवश्यकताएँ और समस्याएँ समान पाई जाती हैं।

- इस बृहत नियोजित प्रदेश में मध्यम स्तरीय प्रदेशों की संख्या निश्चित नहीं होती परन्तु बृहत प्रदेश में नियोजन की दृष्टि से कम से कम दो मध्यम स्तरीय प्रदेशों का होना आवश्यक है। नियोजन की दृष्टि से बृहत प्रदेश को कोई मानक आकार भी नहीं होता है, ये एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है तथा इसका आकार मध्यमस्तरीय प्रदेशों के आकार पर निर्भर करता है।

दांतेवाला कमेटी के अनुसार निम्नलिखित क्रियाएँ विकास खण्ड के स्तर पर नियोजित और कार्यान्वित की जा सकती हैं

- **कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाएँ** (Agriculture and Allied Activities)
- **गौण सिंचाई** (Minor Irrigation)
- **मृदा संरक्षण एवं जल-प्रबन्ध** (Soil Conservation and Water Management)
- **पशुपालन एवं मुर्गी पालन** (Animal Husbandry and Poultry)
- **मत्स्यन** (Fishery)
- **वानिकी** (Forestry)
- **कृषि उत्पादों का प्रक्रमण** (Agricultural Products)
- **कृषि उत्पादन के साधनों की पूर्ति** (Supply of Agricultural Products)
- **कुटीर एवं लघु उद्योग** (Small Scale Industries)
- **स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण तथा स्थानीय जनसंख्या के कौशल में वृद्धि** (Training for Local Youth and Skill Enhancement of Local Population)

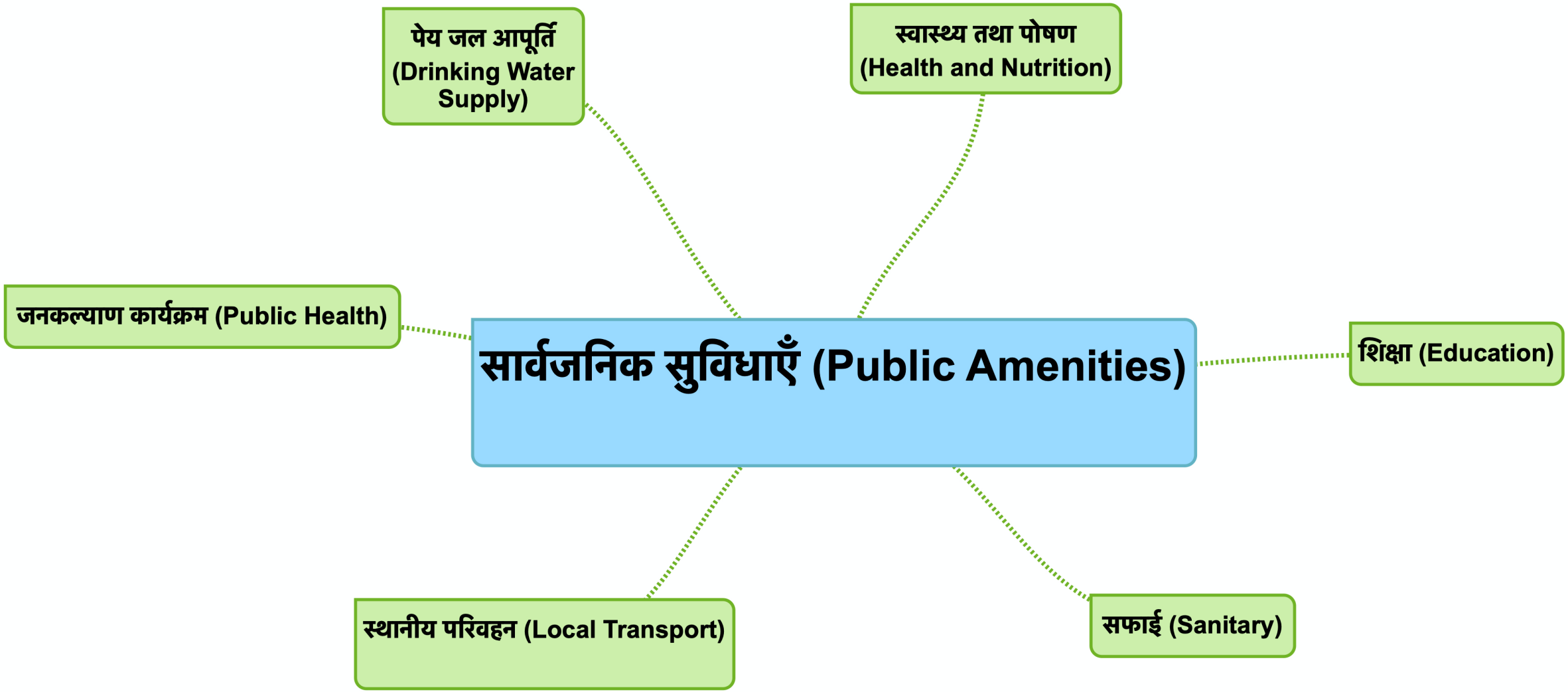
पेय जल आपूर्ति (Drinking Water Supply)
स्वास्थ्य तथा पोषण (Health and Nutrition)
जनकल्याण कार्यक्रम (Public Health)
सार्वजनिक सुविधाएँ (Public Amenities)
शिक्षा (Education)
स्थानीय परिवहन (Local Transport)
सफाई (Sanitary)

Thank YOU